

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:विधि/लाईट्स/5/2019/ 8412-55

दिनांक 15-5-2019

1. अधीक्षक/उपाधीक्षक मुख्यालय कारागार जयपुर
2. लेखाधिकारी मुख्यालय कारागार जयपुर।
3. समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक/केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान,
4. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर,
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
6. महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर

विषय:-लाईट्स सॉफ्टवेयर में लम्बित प्रकरणों का निरस्तारण करने बाबत।

प्रसंग:-राज्य सरकार का पत्र क्रमांक प.14(4)गृह-12/कारा/2016 पार्ट दिनांक 25.4.2019 एवं गृह (ग्रुप-1) विभाग से प्राप्त अ.शा.टीप क्रमांक प.4(7)गृह-1/2015 पार्ट दिनांक 23.4.2019 एवं न्याय विभाग का पत्रांक प.2(3)सामान्य/न्याय/2016 दिनांक 14.2.2019

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि लाईट्स सॉफ्टवेयर में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में दिनांक 23.04.2019 को संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग की ओर से श्रीमान डी.एल.आर. साहब उपस्थित हुए। बैठक में 20 वर्ष से अधिक लम्बित प्रकरणों की टाइटल वाईज सूचना तथा दिनांक 01.08.2017 के बाद के प्रकरणों को LITES की SITE पर ही अपलोड कराने के निर्देश दिये हैं।

अतः आपके कार्यालय से संबंधित लम्बित प्रकरणों का प्रासंगिक पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथासमय लाईट्स वेबसाइट पर अपडेशन/वेलीडेशन करावें एवं दिनांक 01.08.2017 के बाद के न्यायिक प्रकरणों को LITES की SITE पर अपलोड कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित करें ताकि वांछित सूचना राज्य सरकार को भिजवाई जा सके।

कृपया पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(विक्रम सिंह कर्णावत)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. शासन उप सचिव, गृह(ग्रुप-12) विभाग को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. उप महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर/जोधपुर/उदयपुर को प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रतियाँ प्रेषित कर लेख है कि अपनी रेंज के अधीन समस्त कारागृह/कार्यालय प्रभारियों को उक्त निर्देशों की पालना करने हेतु पाबंद करने का श्रम करावें।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार
3. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा मुख्यालय कारागार जयपुर को प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की आवश्यक कार्यवाही करावें। संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

दिनांक 15-5-2019

क्रमांक:विधि/लाईट्स/5/2019/ 8412-55

1. अधीक्षक/उपाधीक्षक मुख्यालय कारागार जयपुर
2. लेखाधिकारी मुख्यालय कारागार जयपुर।
3. समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक/केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान,
4. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर,
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
6. महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर

विषय:-लाईट्स सॉफ्टवेयर में लम्बित प्रकरणों का निरस्तारण करने बाबत।

प्रसंग:-राज्य सरकार का पत्र क्रमांक प.14(4)गृह-12/कारा/2016 पार्ट

दिनांक 25.4.2019 एवं गृह (गुप-1) विभाग से प्राप्त अ.शा.टीप

क्रमांक प.4(7)गृह-1/2015 पार्ट दिनांक 23.4.2019 एवं न्याय

विभाग का पत्रांक प.2(3)सामान्य/न्याय/2016 दिनांक 14.2.2019

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि लाईट्स सॉफ्टवेयर में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में दिनांक 23.04.2019 को संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग की ओर से श्रीमान डी.एल.आर. साहब उपस्थित हुए। बैठक में 20 वर्ष से अधिक लम्बित प्रकरणों की टाईटल वार्डज सूचना तथा दिनांक 01.08.2017 के बाद के प्रकरणों को LITES की SITE पर ही अपलोड कराने के निर्देश दिये हैं।

अतः आपके कार्यालय से संबंधित लम्बित प्रकरणों का प्रासंगिक पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथासमय लाईट्स वेबसाइट पर अपडेशन/वेलीडेशन करावें एवं दिनांक 01.08.2017 के बाद के न्यायिक प्रकरणों को LITES की SITE पर अपलोड कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित करें ताकि वांछित सूचना राज्य सरकार को भिजवाई जा सके।

कृपया पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

ह

(विक्रम सिंह कर्णावत)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. शासन उप सचिव, गृह(गुप-12) विभाग को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. उप महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर/जोधपुर/उदयपुर को प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रतियाँ प्रेषित कर लेख है कि अपनी रेंज के अधीन समस्त कारागृह/कार्यालय प्रभारियों को उक्त निर्देशों की पालना करने हेतु पाबंद करने का' श्रम करावें।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार
3. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा मुख्यालय कारागार जयपुर को प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की आवश्यक कार्यवाही करावें। संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Vijay
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

11

380
29/4/19

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

गृह(ग्रुप-12/जेल) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
हायरो संख्या 2483
दिनांक 24/04/19

विषय:- लाइट्स सॉफ्टवेयर में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करने बाबत।

सन्दर्भ:- न्याय विभाग के पत्र क्रमांक प.2(3)बैठक/न्याय/2016 दिनांक 15.03.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन हैं कि दिनांक 23.04.2018 को संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग के कक्ष में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न निर्देश प्रदान किये गये:-

1. 20 वर्ष से अधिक के लम्बित प्रकरणों की Title Wise सूचना जो दिनांक 14.02.2019 के Latter में Format दिया गया है, उसमें दिया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा प्रकरण वार सूचनाओं की समीक्षा की जावे। (प्रति सलग्न)

2. दिनांक 01.08.2017 के बाद के प्रकरणों को LITES की Site पर ही अपलोड किया जावे। पृथक से पत्रावलियां खोलने की आवश्यकता नहीं है।

अतः तदनुसार सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा आगामी बैठक से पूर्व निम्नहस्ताक्षरकर्ता को वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देश प्रदान कर अनुगृहीत करें।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार

24/4/19

24/4/19

24/4/19

श्री गुरुजी भाग्यलाल

(पुंकेश शर्मा)

(पुंकेश शर्मा)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग
विशिष्ट शासन सचिव गृह (गृह रक्षा) विभाग
शासन उप सचिव (कारागार) विभाग।

अशा.टीप क्रमांक : प. 4(7)गृह-1/2015पार्ट
जयपुर, दिनांक 23 APR 2019

राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांक: प.2(2) सामान्य/न्याय/2018

जयपुर, दिनांक 14.02.2019

अतिरिक्त मुख्य सचिव/
शासन प्रमुख सचिव/
शासन सचिव।

विषय:- 20 वर्ष से अधिक लम्बित न्यायिक प्रकरणों की सूची उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक विभागों के लम्बित न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा करने से यह दृष्टिगोचर होता है कि 20 वर्ष से अधिक लम्बित न्यायिक प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में हुई प्रगति आशानुरूप नहीं है।

उक्त वर्णन के पृष्ठभूमि में आपसे अनुरोध है कि सलग्न परिशिष्ट में आपके विभाग (जिसमें विभागाध्यक्ष व प्रशासनिक विभाग के स्तर के उक्त रूप से लम्बित न्यायिक प्रकरण शामिल हैं) से सम्बन्धित सूचना इन्द्राज कर इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को एवं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठक में उक्त प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा करने हेतु नोडल अधिकारी को निर्देशित करने का श्रम करे।

भवदीय

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

शासन सयुक्त सचिव

स्मरण पत्र तृतीय

राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांक: प. 3(1) विविध/न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 23-4-19

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. जिला कलक्टर
(जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

विषय:-विभिन्न निर्णयो, प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति इत्यादि की प्रतियां प्रेषित करने के स्थान पर उन्हें वेबसाईट पर इन्द्राज/अद्यतन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.12.16 एवं 24.03.17 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के प्रभारी-अधिकारी के नियुक्ति आदेश, अवमानना प्रकरण, नोटिस (Notice to show cause), निर्णयों की सूचनाओं की प्रतियां व अन्य सूचनाओं की प्रतियां (Hard copy) न्याय विभाग को प्रेषित की जा रही हैं, जबकि इन्हे न्याय विभाग की वेबसाईट www.lites.law.rajasthan.gov.in पर संबंधित विभागों/कार्यालयों द्वारा अपने स्तर पर ही On-line इन्द्राज/अद्यतन (Entry/updation) किया जाना है, इसके बावजूद उपरोक्त प्रतियां (Hard copy) न्याय विभाग को प्रेषित की जा रही है जो कि समय, संसाधन व श्रम का दुरुपयोग है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने का श्रम करें, कि भविष्य में उक्त सूचनाएँ न्याय विभाग को प्रेषित न की जाकर उन्हें न्याय विभाग की वेबसाईट पर इन्द्राज/अद्यतन करने का कार्य ही किया जाये।

भवदीय

अतिरिक्त मुख्य सचिव

विविध-शासन

21/4.

D:\SO\3(1) Miscellaneous\Justice\2016

29/4/19
Le

Formate for Court Case Pending from more than 20 years

[illegible]